P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-3* (Part-1) November- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों में वैश्वीकरण की भूमिका

हरिचरण अहिरवार
अतिथि विद्वान,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रीवा, म0प्र0

राजकरन चर्मकार
अतिथि विद्वान,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
नवरोजाबाद,उमरिया,
म0प्र0

सारांश

वर्तमान समय में वैश्वीकरण काफी चर्चा में है जिसका प्रभाव मानवीय जीवन के तमाम क्षेत्रों में पड़ रहा है। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैश्वीकरण एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अवधारणा का नाम है जिसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का अध्ययन करके सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण की धारणा विश्व के सभी क्षेत्रों में वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा एक वास्तविक विश्व समुदाय की स्थापना करने की वकालत करती है क्योंकि ऐसा होने से ही विश्व के समस्त लोगों का सर्वपक्षीय टिकाऊ विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।

मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, अन्तर्राष्ट्रीयवाद, विश्व बाजार, मुक्त बाजार।

प्रस्तावना

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं विश्व व्यवस्था में वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह सत्य है कि वैश्वीकरण को समझे बिना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं सम्बन्धों के अंतर सहबंधनों एवं प्रक्रिया को समझ पाना कठिन है। फ्रेंच भाषा में वैश्वीकरण के लिए 'Mondialisation' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के साहित्य में प्रयोग हुआ है। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण की सीमा पार उत्पादों, सेवाओं, पूँजी, लोक सूचना और संस्कृति के प्रभाव बढ़ाने की भूमण्डलीय प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। सामान्यतः वैश्वीकरण एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका प्रभाव मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में पड़ रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए एडवर्ड एस. हरमन कहता है कि, ''वैश्वीकरण विभिन्न सीमाओं के आर–पार कार्पोरेट फैलाव की एक सक्रिय प्रक्रिया भी है तथा साथ ही पार सीमा सुविधाओं और आर्थिक सम्बन्धों की एक संरचना भी है जिसका लगातार विकास हो रहा है तथा जो ज्यों–ज्यों आगे बढ़ रही है त्यों–त्यों परिवर्तित हो रही है''।[1]

राजनीतिक विश्लेषकों का अभिमत है कि, यह अनेक घटनाओं का एक समूह है जो कि एक दूसरे का साथ देते है और जिसमें कोई भी एक पक्ष अन्य पक्षों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। उनके अनुसार अनेक तत्व हैं जो कि आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 'विशेष' बनाते हैं, जैसे कि तीव्रगति की संचार व्यवस्था, बाजार का उदारीकरण तथा उत्पादों और सेवाओं की विश्वव्यापी एकीकरण।

वैश्वीकरण को संसार के विभिन्न लोगों, प्रदेशों और देशों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक संबंधों ने दुनिया को बांध दिया है। डेविड हेल्ड के अनुसार वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं है

सामाजिक संबंधों में खिंचाव

वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि, इससे राष्ट्र–राज्य की सीमाओं से बाहर सामाजिक संबंध निकट आ जाते है। विश्वभर में राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यदि विश्व के किसी एक भाग में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका अन्य भागों पर भी प्रभाव पड़ता है।

प्रवाह की तीव्रता

वैश्वीकरण की एक अन्य विशेषता है पारस्परिक क्रिया और अन्तः संबंधों की तीव्रता जो राष्ट्र–राज्यों की सीमा को भी पार कर जाती है। यह सूचना तंत्र के कारण संभव हो पाया है जहाँ भौतिक दूरी सामाजिक संबंधों में बाधक नहीं बनती।

संस्कृतियों के बीच संबंध

यह दूरस्थ संस्कृतियों के बीच निरन्तरशील पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जुड़ जाती है। इस प्रकार स्थानीय और वैश्विक स्तरों के बीच संबंध बन जाते है।

निरन्तर अन्तर्व्याप्ति

संबंधों की तीव्रता वैश्विक आधारभूत संरचना ने सरल बनाया है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी विभिन्न एजेंसियों जैसे अन्तः सरकारी संगठनों ने राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में ऐसी भूमिका निभाई है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वित्त के स्थायित्व और नियमन के लिए आधार प्रदान किया है तथा विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार का नियमन किया है।[2]

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध–पत्र की प्रकृति विश्लेषणात्मक एवं अनुभवमूलक है। इसमें शोध के द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है तथा तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए पुस्तकालय, सन्दर्भ–ग्रन्थों तथा पत्र–पत्रिकाओं से स्त्रोत सामग्री का संकलन किया गया है, इसके अतिरिक्त इन्टरनेट के माध्यम से अध्ययन विषय के अनुरूप सामग्री संकलित कर शोध–पत्र के प्रमाणिक निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है।

वैश्वीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयवाद

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम वैश्वीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयवाद में अन्तर को स्पष्ट समझ लें। आज तक हम अन्तर्राष्ट्रीयवाद शब्द का प्रयोग करते रहे है जिससे हमारा अर्थ रहा है, राष्ट्रों में आपसी सम्बन्धों का विकास। दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीयवाद वह धारणा है जो सभी राष्ट्रों में सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की वकालत करती है। आजकल हम अन्तर्राष्ट्रीयवाद के स्थान पर वैश्वीकरण शब्द का अधिक प्रयोग करने लगे हैं और इससे भाव यह है कि सभी देशों में विद्यमान सीमाओं से ऊपर उठ कर वस्तुओं, सेवाओं, ज्ञान और व्यापार का खुला आदान–प्रदान और प्रसार।

जहां कि अन्तर्राष्ट्रीयवाद की धारणा राष्ट्रीय व्यवस्था के तथ्य पर आधारित रही है और इस बात की वकालत करती है कि विश्व का विकास एक विश्व गांव के स्वरूप में किया जाना चाहिए, जिसमें लोग और उनकी संस्थाएँ खुले रूप में एक दूसरे से सम्बन्ध बनाने और वस्तुओं, सूचनाओं और ज्ञान का आदान–प्रदान करें। विश्वसनीय तौर पर वैश्वीकरण की धारणा अन्तर्राष्ट्रीयवाद की धारणा से अधिक विकसित है। वैश्वीकरण की धारणा के अधीन यह प्रयास किया जा रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सम्बन्धों की स्थापना और विकास के लिए सभी देशों के सभी लोगों के लिए एक समान नियम, सुविधाओं और अवसरों को व्यापक किया जाए। वैश्वीकरण विश्व के सभी लोगों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों एवं सहयोग को विस्तृत करने की धारणा है।

वैश्वीकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

वैश्वीकरण के विविध आयामों में राजनीतिक दृष्टि से चर्चा करें तो वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को शिथिल किया है, साथ ही राजनीतिक, शासन और अभिशासन का विप्रदेशीकरण किया है। इस कारण निम्नलिखित 6 प्रतिक्रियाओं ने जन्म लिया है –

1. राष्ट्र–राज्यों की प्रभुता का पतन।
2. प्रादेशिक सीमाओं से निकलकर पूँजी, जनता और तकनीकी के व्यापक प्रवाह से राष्ट्र–राज्यों की शक्ति में कटौती।
3. वैश्विक अभिशासन का उदय।
4. महाशक्ति का उदय।
5. भू–राजनीतिक क्षेत्र से भू–आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन।
6. अन्तर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका में व्यापक वृद्धि।

ये सभी प्रक्रियाएँ जटिल रूप से परस्पर जुड़ी हुई है और एक–दूसरे को मजबूत करती है। डेनियल बेल ने सही कहा है वैश्वीकरण की तीव्र लहरों से अब आंतरिक–बाह्य विभाजन भी समाप्त हो गया है, यहाँ तक कि अब प्रादेशिक विभाजन इतना अप्रासंगिक हो गया है कि विश्व पूँजी बाजार विनिमय दरों को नियंत्रित करने लगा है।[3] वैश्वीकरण के कारण अन्तर्संबंधों का स्तर इतना बढ़ गया है कि किसी एक राष्ट्र में लिए गये निर्णय का असर दूसरे राष्ट्र पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी मंदी के परिणामस्वरूप एशिया में सॉफ्टवेयर व्यावसासियों की नौकरियों को हानि पहुँची। इस परिदृश्य में लगता है कि राज्य की प्रभुता का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया क्योंकि एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह तो मीलों दूर स्थित किसी राष्ट्र की घटनाओं का परिणाम है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे नीतियाँ जिन्हें परम्परागत रूप से आंतरिक नीतियाँ कहा जाता है, वे किसी बाहरी तत्व द्वारा नियंत्रित हो रही है जो उस राष्ट्रीय सरकार के हाथों में अधिक नहीं रह गये हैं। कुछ लोग इसे राज्य की उदारता और दुर्बलता का नाम देते है तो कुछ ऐसे राज्य की निष्क्रियता मानते है। इस वैश्विक शक्ति को केवल कम्प्यूटर तकनीकी से प्रवर्तित नहीं कहा जा सकता। 1980 और 1990 के दशक में पूँजी पर से अन्तर्राष्ट्रीय बाधाओं को हटाने में बाजार और नवउदारवादी राजनीतिक निर्णयों ने भी मदद की है।

अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण अन्तर्सरकारी संस्थाएँ कर रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, नीतियों, सिद्धांतों और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का संचालन करती है। इस परिदृश्य ने इन अन्तर्सरकारी संस्थाएँ के सदस्य–राज्यों को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रवर्तित संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम एक सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे इस अन्तर्सरकारी संस्थाओं के बारे में कभी सुना भी नहीं और उसे यह भी नहीं मालूम यह सब इस प्रकार क्यों चल रहा है। विश्व अब एक संक्रमणकालीन अवस्था के दौर से गुजर रहा है, जहाँ राष्ट्र–राज्य अपनी परम्परागत भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं हैं। शायद यह वैश्विक अभिशासन की दिशा में प्रगति है। कुछ लोग इसे राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीयकरण का भी नाम देते है। अतः हम उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं

ने अधिराष्ट्र शक्ति का स्तर प्राप्त कर लिया है। विश्व व्यापर संगठन इसका उदाहरण है। एक देश के अधिकारी वर्ग और निर्वाचित राजनीतिज्ञों की नीतियाँ इन अन्तर्सरकारी संस्थाओं से प्रभावित होती हैं। इन अन्तर्सरकारी संस्थाएँ की वैश्विक अभिशासन की भूमिका ने अधिकारियों या नौकरशाहों के पारसरकारी गठबंधन का निर्माण किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब नीतियों के निर्णय में निर्वाचित राजनीतिज्ञों या राज्य की केन्द्रीय सरकार की अधिक भूमिका नहीं रह गई है। वैश्वीकरण के समीक्षकों का कहना है कि अब उत्तर विश्व का वैश्विक सरकार में अधिक बोलबाला है और विश्व की महाशक्तियों के प्रभाव के कारण विकासशील दक्षिण विश्व की प्रभुता का अन्त हो गया है। इस वैश्वीकरण की प्रवृत्ति की एक अन्य विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियों का प्रभुत्व। समकालीन वैश्विक राजनीति की एक अन्य विशेषता है – भू–राजनीति से भू–अर्थनीति में परिवर्तन। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक युद्धों और हमलों से अन्तर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ते रहे जिसमें एक राष्ट्र अपनी राजनीतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता रहा। यह सैनिक सामर्थ्य शक्ति और आधिपत्य के बराबर था। वह शक्ति और अधिपत्य ही था जिसे राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता रहा। यह सैनिक सामर्थ्य शक्ति और आधिपत्य के बराबर था। वह शक्ति और अधिपत्य ही था जिसे राष्ट्र मित्र गुट बनाकर या विश्व युद्धों और शीत युद्ध के जरिये विश्व में फैलाना चाहते थे। मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच विवाद ने विश्वयुद्धों को जन्म दिया जिसमें प्रत्येक पक्ष ने अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए अपने पूरे जोर से दूसरे पक्ष के जीवन और संपत्ति का विनाश तक कर दिया। इसी प्रकार शीत युद्ध ने पूँजीवादी और साम्यवादी शक्तियों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव किया। दोनों पक्ष एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे और साम्यवादी शक्तियों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव किया। दोनों पक्ष एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे और इस पागलपन की दौड़ में दोनों ही प्रकार के युद्धों में आर्थिक टकराव किया। दोनों पक्ष एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे और इस पागलपन की दौड़ में दोनों ही अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए विस्तारवादी नीतियों में संलग्न रहे। इन दोनों ही प्रकार के युद्धों में आर्थिक और मानव संसाधनों की भरपूर हानि हुई। शायद यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से महाशक्तियों ने यह अनुभव किया कि शस्त्रों की दौड़ में उन्हें अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की कोशिशों की बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके लिए समृद्धि लाये। अब यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय पहचान सैनिक विजय की बजाय बाजारी प्रतियोगिता से परिभाषित होती है। बाजार प्रतियोगिता ने अनेक देशों में आर्थिक रूप से परस्पर निर्भरता कायम की है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेशिक आर्थिक गुटों का निर्माण हुआ।

निष्कर्ष

आवश्यकता वैश्वीकरण की समाप्ति की नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके नाम पर किये जा रहे कुछ स्थानीय तथा संकीर्ण लक्ष्यों को विश्व स्तरीय आन्दोलनों से रोका जाये। वैश्वीकरण को प्रशासित कर इसे लागू किया जाना चाहिए। विश्व सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता है। कई एक ऐसे क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं तथा प्रयत्न विद्यमान हैं, जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को शक्तिशाली एवं सफल बनाने की ओर कार्य कर तो रहे है परन्तु इनको अधिक सक्रियता तथा कुशलता से कार्य करने की आवश्यकता है। विभिन्न स्तरों पर आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है। यह समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक विशेषता भी है और आवश्यकता भी है। यह ठीक है कि इस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले कई खतरे भी मौजूद हैं जैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, व्यापारिक विशिष्ट वर्ग की कम्पनियों तथा विकसित देशों द्वारा किये जा रहे विश्व व्यापार संगठन पर हावी होने का प्रयास। इन खतरों का सामना करने के लिये विश्व स्तर पर सहयोग करने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के सम्भावित खतरों को विश्व स्तर पर विश्व स्तरीय प्रयासों और उपायों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। ऐसा एकदम से नही हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व स्तर के प्रशासन के लिये नई संरचनाओं की स्थापना की जाये। वैश्वीकरण के पुनर्नियमन के द्वारा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास करने के प्रयास किये जायें तथा राज्यों और व्यक्तियों पर हो रहे हानिकारक सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक प्रभावों को समाप्त किया जाये। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके नकरात्मक और हानिकारक प्रभावों की समाप्ति करके इसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा समृद्धि की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया बनाया जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *घई यू.आर., 2015, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर*
2. *भारद्वाज डॉ. रामदेव, 2014, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक राजनीतिक मुद्दे, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल*
3. *भारद्वाज डॉ. रामदेव, 2014, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक राजनीतिक मुद्दे, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल*
4. *फड़िया डॉ. बी.एल, 2006, उच्चतर लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा*
5. *भारद्वाज डॉ. रामदेव, 2014, राजनय एवं मानवाधिकार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल*
6. *लक्ष्मीकांत एम. 2008, लोक प्रशासन, टाटा मैग्रा–हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली*
7. *कुमार डॉ. अशोक, प्रतियोगिता दर्पण (अतिरिक्तांक), उपकार प्रकाशन, आगरा।*